

न्यायालय राजस्व मण्डल, म०प्र० ग्वालियर

समक्ष

एम०के०सिंह

सदस्य

अपील प्रकरण क्रमांक 1206-एक/2012 - विरुद्ध आदेश  
दिनांक 5-8-2010 - पारित द्वारा -- अपर आयुक्त, चम्बल  
संभाग, मुरैना - प्रकरण क्रमांक 22/2007-08 अपील

1- गोपाल पुत्र मांगीलाल

2- बद्रीलाल पुत्र गोपाल

3- महावीर पुत्र गोपाल

तीनों निवासी इच्छापुर

तहसील व जिला श्योपुर कलॉ

---अपीलांट्स

विरुद्ध

मॉंगीलाल पुत्र स्व० मोतीलाल माली

ग्राम इच्छापुर तहसील श्योपुर कलॉ

जिला श्योपुर कलॉ, मध्य प्रदेश

---रिस्पान्डेन्ट

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी)

(अनावेदक के अभिभाषक श्री मुकेश वेलापुरकर)

आ दे श

(आज दिनांक 3 - 2 - 2016 को पारित)

यह अपील मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की  
धारा 44 के अंतर्गत अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना द्वारा  
प्रकरण क्रमांक 22/2007-08 अपील में पारित आदेश  
5-8-2010 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।



R

2/ प्रकरण का सारौंश यह है कि अनावेदक ने इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया कि ग्राम इच्छापुरा की भूमि सर्वे क्रमांक 428/1 रकबा 8 वीघा 11 विसवा (आगे जिसे वादग्रस्त भूमि सम्बोधित किया गया है) उसके स्वर्गीय पिता मोतीलाल को भूदान बोर्ड से पट्टे पर मिली थी जिस पर उन्होंने खेती की। जब वह नावालिग का था, मोतीलाल की मृत्यु हो गई उसी समय मौजा पटवारी से मिलकर गोपाल माली ने फर्जी रजिस्ट्री कलेक्टर की अनुमति के बिना अपने लड़कों के नाम करा ली एवं पटवारी ने फर्जी मिसल नंबर डालकर नामान्तरण भी कर दिया। अब गोपाल ने भूमि पर जबरन कब्जा कर लिया है जांच कर जमीन वापिस दिलाई जावे। कलेक्टर श्योपुर कलॉ ने प्रकरण क्रमांक 767 बी-121/2002-03 पंजीबद्ध किया तथा पक्षकारों की सुनवाई उपरांत आदेश दिनांक 15-10-2007 पारित किया तथा आवेदक का दावा निरस्त कर दिया। इस आदेश के विरुद्ध अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना के समक्ष अपील होने पर प्रकरण क्रमांक 22/2007-08 अपील में पारित आदेश 5-8-2010 से अपील स्वीकार कर कलेक्टर श्योपुर का आदेश दिनांक 15-10-2007 निरस्त किया तथा तहसीलदार श्योपुर को निर्देश दिये गये अपीलार्थी (इस न्यायालय का रिस्पा0) का आवेदन आने पर नामान्तरण की कार्यवाही संपादित की जाय। इसी आदेश से दुखी होकर यह अपील की गई है।

3/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्कों पर विचार करने के साथ ही उनके द्वारा प्रस्तुत लेखी बहस एवं अधीनस्थ न्यायालयों के प्रकरणों का अवलोकन किया गया।

4/ अपीलांट के अभिभाषक का तर्क है कि अपर आयुक्त द्वारा सूचना पत्र भेजे बिना एवं सुनवाई का अवसर दिये बिना एकपक्षीय आदेश पारित किया है जो नैसर्गिक न्याय के विरुद्ध है। इस सम्बन्ध में अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना के प्रकरण क्रमांक 22/2007-08 अपील के अवलोकन पर पाया गया कि इस प्रकरण



R

में पृष्ठ क्रमांक 79, 80 पर आवेदकगण को पेशी 17.4.2088 की सुनवाई हेतु भेजे गये सूचना पत्र संलग्न है जिसकी प्रति निर्वाह उपरांत वापिस नहीं लौटी है। इसके बाद पुनः 24.7.20087 की पेशी के सूचना पत्र भेजे गये जिसकी एक प्रति बद्रीलाल ने स्वयं की प्राप्त की है एवं गोपाल की प्रति भी बद्रीलाल ने प्राप्त की है क्योंकि सूचना पत्र के पीठ पृष्ठ पर बद्रीलाल के निशानी अँगूठा लगा है एव ग्रामीण भगवानदास गवाह के समक्ष जमादार तहसील श्योपुर ने सूचना पत्र का निर्वहन किया है तदाशय की टीप जमादार तहसील श्योपुर ने लगाई है। इसके बाद भी अपीलांट्स यह तर्क कि उन्हें सुने बिना अपर आयुक्त ने एकपक्षीय आदेश पारित किया है अविश्वसनीय है।

5/ अपीलांट्स के अभिभाषक का तर्क है कि विक्रय पत्र की वैधता की जांच करने का अधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं है। वादग्रस्त भूमि भूदान बोर्ड से पट्टे पर दी गई भूमि है। मध्यप्रदेश शासन ने भूदान बोर्ड गठित कर गरीब एवं कृषि श्रमिकों को आजविका चलाने के लिये भूमि दिये जाने के नियम बनाये थे वर्तमान में भूदान बोर्ड समाप्त है और वादग्रस्त भूमि भूदान पट्टे की है। मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 165 की उप धारा 7 व्यवस्था करती है कि विक्रय कानून के उपबंधों के विरुद्ध किया गया जो आरंभ से ही व्यर्थ एवं शून्य है ऐसे ही न्यायिक दृष्टांत इथोवा बनाम भागचंद 1964 ज0ला0ज0 606 एवं केशवा विरुद्ध म0प्र0राज्य 1996 रा0नि0 175 (SC) के हैं। भूमि का विक्रय पत्र विधि के प्रभाव से शून्य एवं अकृत श्रेणी का होने से अपीलीय न्यायालय संहिता की धारा 165 के अधीन सशक्त होने से तदाशय का आदेश पारित कर सकता है जिसके कारण अपीलांट्स के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत यह तर्क भी स्वीकार योग्य नहीं है।

6/ अपीलांट्स के अभिभाषक ने तर्क भी दिया कि कलेक्टर श्योपुर ने प्रकरण क्रमांक 4/03-04 अ 21 में पारित आदेश दिनांक



5-1-04 से वादग्रस्त भूमि के विक्रय की अनुमति प्रदान की है इसके बाद भी अपर आयुक्त ने विक्रय पत्र को दरकिनार किया है। प्रकरण के अवलोकन से मूल विवाद भूदान भूमि के पट्टाग्रहीता मोतीलाल द्वारा वादग्रस्त भूमि आवेदकगण को विक्रय पत्र दिनांक 6-1-77 के विक्रय पर उत्पन्न हुआ है जबकि कलेक्टर श्योपुर ने विक्रय अनुमति 5-1-04 को प्रदान की है जिसके कारण 5-1-04 का विक्रय अनुमति आदेश विक्रय पत्र दिनांक 6-1-77 पर प्रभाव नहीं डालता। भूदान पट्टाग्रहीता मोतीलाल की मृत्यु 1974 में होना कलेक्टर श्योपुर ने आदेश दिनांक 15.10.2007 के पद 6 में बताई है, इन्हीं कारणों से अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना द्वारा प्रकरण क्रमांक 22/2007-08 अपील में पारित आदेश 5-8-2010 से लिये गये निर्णय में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की गुंजायश नहीं है। वैसे भी विद्वान अपर आयुक्त ने माननीय वरिष्ठ न्यायालयों के आदेशों का अनुसरण करते हुये बोलता हुआ आदेश पारित किया है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की गुंजायश नहीं है।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपील सारहीन पाये जाने से निरस्त की जाती है एवं अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना द्वारा प्रकरण क्रमांक 22/2007-08 अपील में पारित आदेश 5-8-2010 विधिवत् होने से यथावत् रखा जाता है।

(एम०के०सिंह)

सदस्य

राजस्व मण्डल

मध्य प्रदेश ग्वालियर

R